BCCI BULLETIN

Vol. 51 | FEBRUARY 2020 | No. 2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

मांग चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य से मिला

'विवाद से विश्वास' विधेयक में हो संशोधन

सीबीडीटी के सदस्य श्री प्रभाश शंकर को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में उपस्थित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एण्ड झारखण्ड) श्री वीरेन्द्र सिंह एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (नयी दिल्ली) के सदस्य प्रभाश शंकर को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में मिल कर प्रत्यक्ष कर से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रभाश शंकर दिनांक 12 फरवरी 2020 को पटना पहुँचे थे। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि चैम्बर द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य से यह अनुरोध किया गया कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गयी **'विवाद से विश्वास'** योजना के विधेयक में कुछ आवश्यक संशोधन किये जाएं, जिससे करदाता इस योजना का लाभ उठा सकें।

विवाद से मिली राहत : इससे एक ओर तो करदाताओं को विवाद से राहत मिलेगी और दूसरी ओर सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, वरीय सदस्य राजेश खेतान, सुनील सराफ, सुबोध जैन एवं आशीष प्रसाद शामिल थे।

ज्ञापन के मुख्य बिंदु : • आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलेट फोरम में अपील के लिए वैधानिक समय सीमा इस प्रकार है- आयकर आयुक्त अपील के लिए 30 दिन, आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 60 दिन एवं उच्च न्यायालय के लिए 120 दिन। अधिकाधिक कर विवाद के मामलों के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि 'विवाद से विश्वास' की अंतिम तिथि, जो 31 जनवरी 2020 थी, उसमें आवश्यक संशोधन करके 31 मार्च तक किया

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में उपस्थित सी बी डी टी के सदस्य श्री प्रभाश शंकर एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

शेष पृष्ठ 3 पर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोक सभा में 01 फरवरी 2020 को पेश किये गये बजट 2020–21 से काफी अपेक्षाएँ हैं कि आम बजट से देश को आर्थिक मंदी से उबारने में सहायता मिलेगी। आयकर स्लैब में परिवर्तन से भी कुछ लोगों को राहत मिल सकेगी, जो इस विकल्प (Option) को अपनायेंगे लेकिन इससे बचत पर प्रभाव पड़ेगा।

बजटीय घोषणाओं से किसानों एवं छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हलांकि बिहार के लिये इस बजट में कोई प्रस्ताव नहीं होने से व्यवसायियों में थोड़ी मायूसी अवश्य हुई है। बिहार की आम जनता के साथ–साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी, क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयल्टी के मद में राज्य को काफी हानी हुई है।

आम बजट में डिविडेन्ट डिस्ट्रीब्युशन टैक्स को कम्पनी के बदले व्यक्तिगत किये जाने, सूक्ष्म इकाईयों के लिए 5 करोड़ तक ऑडिट से छूट, किसानों के लिए 16 सूत्री लाभकारी योजनाएँ, निवेश को आसान बनाने के लिए इन्वेस्टमेन्ट क्लीयरेंस सेल की स्थापना, देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को अपग्रेड करने एवं तेजस जैसी ट्रेनों से जोड़ने, बिजली उपभोक्ताओं को सप्लायर चुनने का अधिकार, टैक्स पेयर्स की सुविधा हेतु टैक्स पेयर्स चार्टर का गठन, प्रत्यक्ष कर में ''विवाद से विश्वास'' की योजना एवं बैंक गारंटी की सीमा को पाँच लाख किये जाने जैसी घोषणाएँ स्वागत योग्य है।

बिहार बजट 2020–21 को माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 को पेश किया गया। राज्य सरकार ने प्रथम बार ग्रीन बजट पेश किया है। इससे राज्य के स्थायी एवं सतत् विकास में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त मानव विकास के हित में यह बजट महत्वपूर्ण सावित होगा। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 6 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

बजट में नये मेडिकल कॉलेज खोलने, अस्पतालों में बेड एवं अन्य सुविधाएँ बढ़ाने, वर्षा जल संचय, नये सड़कों का निर्माण, बिहटा एवं पटना एयरपोर्ट के विकास पर जोर दिया गया है जो राज्य के व्यापारियों के लिए लाभकारी होगा। सड़कों के विकास से राज्य में व्यापार की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त चैम्बर ने बजट पूर्व सरकार को कुछ सुझाव समर्पित किये थे, जिसपर सरकार को विचार करना चाहिए था।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 71वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक 07 फरवरी 2020 को माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में मैं भी आमंत्रित था। मैने भी अपने सुझाव दिये।

माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में टैक्सेशन से संबंधित समस्याओं पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक 08 फरवरी 2020 को मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में बजट पूर्व बैठक हुई। इस बैठक में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ जिसमें मेरे अलावा महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, जीएसटी उप–समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री सांवल राम ड्रोलिया, श्री गणेश खेमका, श्री डी.बी. गुप्ता एवं श्री राजीव अग्रवाल सम्मिलित थे।

मेरे साथ चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल श्री प्रभाश शंकर, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से राजस्व भवन, पटना में दिनांक 12 फरवरी 2020 को मिला। इस अवसर पर आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल में कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सुबोध जैन, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष प्रसाद शामिल थे। श्री प्रभाश शंकर को एक ज्ञापन भी समर्पित किया गया और ''विवाद से विश्वास'' विधेयक में आवश्यक संशोधन की मांग की गयी। इसके अतिरिक्त कई विन्दुओं पर श्री प्रभाश शंकर का ध्यान आकृष्ट कराया गया।

दी इकोनॉमिक टाईम्स एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 14 फरवरी 2020 को "SME GROWTH SUMMIT" का आयोजन होटल मौर्या, पटना में किया गया। जिसमें मैं पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुआ और अपने विचार भी रखे।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया का वार्षिक आम सभा –सह–सम्मान समारोह दिनांक 16 फरवरी 2020 को गया में सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 25 वर्षो से कुशल नेतृत्वकर्त्ता एवं संरक्षक डा0 कौशलेन्द्र प्रताप एवं डॉ0 अनूप कुमार केडिया को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यो हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दो प्रतिनिधियों को भेजकर, मेमेन्टो भेंट कर उनको सम्मानित किया गया।

चैम्बर प्रांगण में दिनांक 23 फरवरी 2020 को प्रभात प्रकाशन के सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार श्री सुबोध कुमार नंदन की सद्यः प्रकाशित पुस्तक ''बिहार के ऐतिहासिक गुरूद्वारे'' का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में बिहार के 22 गुरूद्वारों की जानकारी एवं विवरण है। यह पुस्तक सिख समुदाय के लिए तोहफा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त और भी चैम्बर की गतिविधियाँ हुई हैं जिसे इस बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित किया गया है।

बन्धुओं, हर वर्ष की भांति दिनांक 7 मार्च 2020 को चैम्बर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है।

होली की शुभकामनाओं सहित,

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

पृष्ठ 1 का शेष

सीबीडीटी के सदस्य श्री प्रभाश शंकर (बायें)। विचार-विमर्श हेतु उपस्थित चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह (दायें)।

जाये, जिससे कि जो करदाता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, समय सीमा के अंदर अपील कर सकें। • कर विवाद समाधान योजना 1998 की तरह जिस प्रकार से आयकर आयुक्त के यहाँ यू/एस 264 के अधीन लंबित मामलों का विस्तार किया गया था। उसी प्रकार से आवश्यक संशोधन कर योजना का भी विस्तार किया जाये। • 'विवाद से विश्वास' योजना की बड़े पैमाने पर सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कर विवाद समाधान योजना 1998 की तहत कर निर्धारण की प्रक्रिया को भी वर्तमान योजना में शामिल किया जाये। • करदाताओं को यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि अपीलेट ऑथरिटी के समक्ष उनकी जो भी लंबित मामले हैं उन सभी का कर भुगतान कर विवादों का निपटारा करा लें।

(साभार : प्रभात खबर, 13.2.2020)

कर्ज देने का गिर रहा बैंकों का ग्राफ

डिप्टी सीएम मोदी की अध्यक्षता में एसएलबीसी की हुई 71वीं बैठक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अध्यक्षता करते माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, विभागीय अधिकारीगण एवं बैंकों के अधिकारीगण।

राज्य के सभी बैंकों का आम लोगों को कर्ज देने में लगातार तीन साल से ग्राफ गिरता जा रहा है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब है। इस बार एसीपी यानी लोन बांटने की स्थिति अब तक के न्यूनतम स्तर 54.58 प्रतिशत पर पहुँच गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंकों का सीडी (साख-जमा) अनुपात घटकर 42.98 प्रतिशत पर पहुँच गया है डिप्डी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी 7 फरवरी 2020 को शहर में आयोजित राज्यस्तरीय बैंकस कमेटी (एसएलबीसी) की 71वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डिप्टी सीएम ने राज्य में बैंकों के खराब प्रदर्शन पर सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए बैंकों को

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अपना सुझाव देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये के ऋण बांटने का जो लक्ष्य बैंकों को दिया गया है, उसे युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा करें। बचे हुए लगभग डेढ़ महीने में 95 फीसदी तक लक्ष्य हासिल करने की पुरजोर कोशिश करें।

पिछले तीन साल में इसके लक्ष्य में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है। 2017 में 66.56 प्रतिशत, 2018 में 57.40 और 2019 में घटकर 54.58 प्रतिशत पर पहुँच गया।

इसके अलावा 2019 में राज्य का सीडी (साख-जमा) अनुपात भी घटकर 42.98 प्रतिशत हो गया है। दिसम्बर 2018 में सीडी रेसियो 43.18 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में यह 44.09 प्रतिशत था।

बांका, जहानाबाद, नालन्दा, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी व भागलपुर समेत 10 जिले ऐसे हैं, जहाँ एसीपी का प्रतिशत सबसे खराब है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित हुए एवं अपने सुझाव भी दिये। **(साभार : प्रभात खबर, 8.2.2020)**

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बजट पूर्व बैठक में चैम्बर की सहभागिता

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधित बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता करते माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। साथ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, वित्त विभाग के पधान सचिव श्री एस. सिद्धार्थ, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के चेयरयैन श्री अशोक कुमार घोष एवं अन्य।

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बजट पूर्व बैठक माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में दिनांक 06 फरवरी 2020 को सचिवालय सभा कक्षा में आहूत हुई। उक्त बैठक में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी सम्मिलित हुए।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री एस. सिद्धार्थ, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के चेयरमैन श्री अशोक कुमार घोष भी उपस्थित थे। क्रेडाई एवं बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।

चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने एक ज्ञापन भी समर्पित किया। जिसमें • फर्नेस वायल को तीन वर्षों में प्रस्तावित प्रतिबंध का सुझाव दिया जिससे उद्योग क्लिन फ्यूल के लिए अवसंरचना स्थापित कर सकेंगे। • पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं हाजीपुर में स्वच्छ हवा के स्तर को बढ़ाने हेतु प्रयास का तेजी से कार्यान्वयन • चीन की तर्ज पर बिहार के बड़े शहरों में हवा को स्वच्छ करने का टावर स्थापित किया जाये • UNDP एवं कोका-कोला बिभरेजेज प्रा. लि. को पटना के गर्दनीबाग में एक इकाई स्थापित करने को कहा गया है जहाँ 5 टन प्लास्कि अपशिष्ठ को प्रतिदिन निष्पादित करने की क्षमता है। स्वास्थ्य अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन हेतु पटना, मुजफ्फपुर एवं गया में एक-एक इकाइयाँ चालू हैं। • पटना में सीएनजी की आपूर्ति हेतु गेल इंडिया ने 5 में से 3 आउटलेट चालू किये हैं जहाँ डिजल एवं पेट्रोल के

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बजट पूर्व बैठक में अपना सुझाव रखते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, क्रेडाई एवं बिल्डर्स एसोसियेशन के सदस्यगण।

बदले स्वच्छ इंधन की आपूर्ति होगी एवं हवा की गुणवत्ता पटना में अच्छी होगी।

माननीय उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा समय-समय पर हवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है।

इसके तहत पूरे बिहार में 15 वर्षों पुराने सभी डिजल वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही 15 वर्षों से पुराने डिजल आधारित वाहनों को राज्य के पटना नगर निगम और दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ के शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में प्रतिर्वोधित किया गया है।

माननीय उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टैक्सेशन से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित बजट पूर्व बैठक में चैम्बर प्रतिनिधिमंडल हुआ सम्मिलित

बजट पूर्व बैठक में अध्यक्षता करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, विभागीय अधिकारीगण एवं चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

दिनांक 08 फरवरी 2020 को मुख्य सचिवालय के सभागार उप-मुख्यमंत्री-सह-वित्त, वाणिज्य-कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में टैक्सेशन से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु बजट पूर्व एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के साथ-साथ महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, जी.एस.टी. उप समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री गणेश खेमका, श्री डी. बी. गुप्ता एवं श्री राजीव अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। बैठक में एक ज्ञापन भी उप मुख्यमंत्री को समर्पित किया गया।

SME GROWTH SUMMIT
COLLABORATION, KNOWLEDGE KEY TO GROWTH

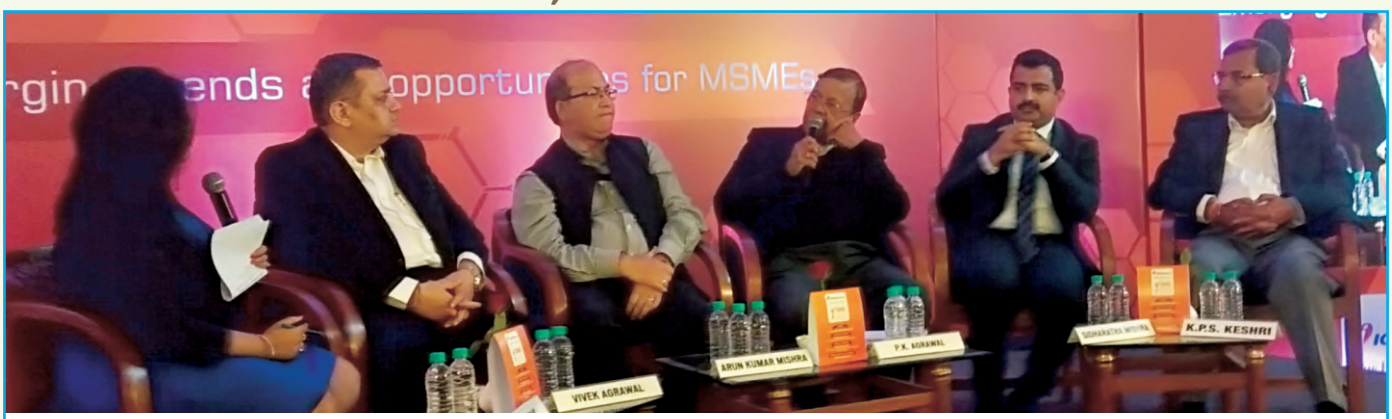

Chambers President Shri P. K. Agrawal sharing his views in the summit (fourth from left), other panelists are also present on the dais.

Exploring new finance avenues, embracing technology & gaining information are must practices for SMEs

A discussion around "Emerging trends and Opportunities in International and Domestic Trade' was organised by ICICI Bank and The Economic Times to delve deeper Into the issues and find some answers on 14.02.2020 at Hotel Maurya.

One of the common issues concerning MSMEs today is GST compliance. From delay in refunds to the lack of coordination between the GST Council and the GST network, entrepreneurs have several complaints regarding the tax. Being a relatively new law and with multiple amendments, MSME owners feel trapped.

But, the fact that it has ushered in transparency and simplified the tax process too can't be discounted. The experts spoke about the special provisions for MSMEs under GST and how they can be availed.

Chamber President Sri P. K. Agrawal is being Honoured in the Summit by presenting a memento (third from right).

Group phonograph of the SME SUMMIT.

In a state like Bihar, brisk financing instead of asking for 40-50 per cent of collateral could work well, believe some experts. But, banks these days mostly work on the digital footprint and MSMEs mostly work with cash, so that again becomes a hindrance. With GST leading to more transparency, this problem may slowly be solved.

MSMEs on their part have to become more tech-savvy. There is no escape from it If they have to survive and thrive. Times are changing and mere investing in the business won't yield results. Use of technology in accounting processes, inventory and service management is equally critical, echoed the experts. The government has introduced schemes that help entrepreneurs investing in technology, and one must benefit from those.

"GST is a relatively new law and most MSMEs are unaware of its nitty-gritties. Multiple amendments and lack of awareness only adds to the confusion leading to mistakes in filing. We urge the authorities to excuse us in case of minor glitches"

P. K. AGRAWAL, President, BCCI

(Details : T. O. I. ,20.2.2020)

अधिक बिजली शुल्क से उद्योगपति परेशान

अधिकतम लोड 5800, बनाया 20,000 मेगावाट का स्ट्रक्चर, खर्च बढ़ा

बिजली की दरों के निर्धारण हेतु बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जन सुनवाई में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का पक्ष रखते चैम्बर के पूर्व उपध्यक्ष एवं उद्योग उप-समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत भवन स्थित कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हुई। इसमें पहले दिन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान चैम्बर द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत कर यह साबित करने का प्रयास किया कि खर्चों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि सूबे में ट्रांसमिशन लॉस बहुत अधिक है। इससे उद्योगपतियों व कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को भी बताया गया।

एक्स्ट्रा कैपिसिटी बनाने से बढ़ा ट्रांसमिशन लॉस

पीक आवर में अब तक पूरे प्रदेश का अधिकतम लोड 5800 मेगावाट गया है, जबकि ट्रांसमिशन कंपनियों ने यहाँ 20,000 मेगावाट का ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। यह जरूरत से तीन गुना से भी अधिक है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग की बैठक में कामर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी को उठाते हुए श्री संजय भरतीया ने कहा कि एकस्ट्रा कैपेसिटी बनाने से ट्रांसमिशन लॉस बढ़ गया है। जिससे बिजली की कीमत बढ़ी है और इस बढ़ी हुए कीमत को आम उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ रहा है। 20 हजार मेगावाट की विशाल क्षमता के कारण प्रति यूनिट बिजली 1.20 रुपया हो गयी है जबकि छह हजार मेगावाट की ही क्षमता बनाने पर यह केवल 36 पैसे होती। इस प्रकार हर कॉमर्शियल उपभोक्ता को प्रति यूनिट 84 पैसे कम देना होता।

– संजय भरतीया
संयोजक, ऊर्जा उप-समिति, बीसीसीआई

सृजित क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल हो तो घटेगी बिजली दर

जरूरत से बहुत अधिक क्षमता बना लेने और उसके 30 फीसदी

बिजली की दरों के निर्धारण हेतु बिहार विद्युत विनियमक आयोग की जन सुनवाई में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का पक्ष रखते ऊर्जा उपसमिति के संयोजक श्री संजय भरतीया।

इस्तेमाल के ही कारण फिक्सड चार्ज बहुत ऊँचा हो गया है। वर्तमान में यह प्रति यूनिट 2.40 रुपये है जबकि प्रति यूनिट बिजली इस्तेमाल करने की दर भी इतनी ही है। इस पर 30 फीसदी का लॉस चार्ज लगाने के बाद यह प्रति युनिट 6.30 रुपये हो जाती है। 1.70 रुपया प्रति यूनिट नेटवर्क चार्ज लिया जाता है जिससे बिजली 8 रुपये प्रति यूनिट होती है और फिर 20 फीसदी क्रॉस सब्सिडी जोड़ने के कारण प्रति यूनिट यह 9.60 रुपये हो जाता है। इतने ऊँचे बिजली दर के कारण ही कोई उद्योगपति यहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहता है। हालांकि एक्ट्रा कैपैसिटी के इस्तेमाल से यदि बचा जाये, तो चार्ज को कम किया जा सकता है।

– सुभाष पटवारी, संयोजक, उद्योग उप-समिति, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 14.2.2020)

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया के वार्षिक आमसभा-सह-सम्मान समारोह में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि हुए सम्मिलित

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया के वार्षिक आम सभा-सह-सम्मान समारोह में मंचासीन चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथिगण।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, गया के दिनांक 16 फरवरी 2020 को संपन्न वार्षिक आमसभा-सह- सम्मान समारोह में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।

उक्त कार्यक्रम में सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25 वर्षों से कुशल नेतृत्वकर्ता एवं संरक्षक डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप एवं डॉ अनूप कुमार केडिया को उनके द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से मेमेन्टो भेंट कर चैम्बर प्रतिनिधिगणों द्वारा सम्मानित किया गया।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप (दाँयें से दूसरे) एवं पूर्व अध्यक्ष डॉ. अनूप कुमार केडिया (बाँयें से प्रथम) को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित करते बिहार चैम्बर के प्रतिनिधिगण।

पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध के साथ जागरुकता भी जरूरी

दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में उपस्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यगण

पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध को लेकर अभियान के तहत बुधवार दिनांक 19.2.2020 को दैनिक भास्कर कार्यालय में आयोजित परिचर्चा में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यगण शामिल हुए। सबने एक मत से कहा कि पोर्न साइट्स समाज के लिए सबसे बीभत्स समस्या बन गई है। इन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही हर स्तर पर जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला होता है, परिवार। यहाँ से ऐसे अभियान को शुरू करना होगा। बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ ही खुलकर सही और गलत के बारे में बताया जाना चाहिए। स्कूलों में अध्यात्म और योग की शिक्षा देने पर भी जोर दिया। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले हर तरह के शो और साइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की।

इस अवसर पर उपस्थित चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कार्यकारणी सदस्य श्री शशि मोहन, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री आलोक पोद्दार, श्री सुनील सराफ, श्री आशीष शंकर, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री संतोष कुमार, श्री आशीष अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री आशीष प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त किये।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर 20.2.2020)

माप-तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकण हेतु माप-तौल विभाग का शिविर चैम्बर में आयोजित

शिविर में माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकण करते विभाग के अधिकारी।

चैम्बर के अनुरोध पर माप-तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकण हेतु माप-तौल विभाग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2020 को चैम्बर प्रांगण में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने अपने माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकण कराया।

चैम्बर अध्यक्ष द्वारा नर्वदा इन्टरप्राइजेज का उद्घाटन

"नर्वदा इनप्राइजेज" का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं नर्वदा इन्टरप्राइजेज के डायरेक्टर, जे. पी. वर्मा, ई. विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य।

"नर्वदा इन्दरप्राइजेज" के उदघाटन के अवसर पर उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री जे. पी. वर्मा, ई. विजय कुमार सिन्हा एवं अन्य।

इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर (पावर एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) का पूर्ण रख-रखाव एवं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मरम्मती कार्य की चलन्त सेवाएं प्रदान करने वाली एजेन्सी 'नर्वदा इन्टरप्राइजेज' न्यू वेंचर का उद्घाटन दिनांक 8 फरवरी 2020 को न्यू पटना क्लब में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के कर-कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर नर्वदा इन्टरप्राइजेज के डायरेक्टर ई० विजय कुमार सिन्हा, प्रोमोटर चार्टर्ड इंजीनियर एवं रजिस्टर्ड वेल्युअर तथा ई० जगदीश प्रसाद वर्मा, चार्टर्ड इंजीनियर सहित कई लोग उपस्थित थे।

नर्वदा इन्टरप्राइजेज के द्वारा ट्रांसफर्मर रख-रखाव के अलावा भविष्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सेल की मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कार्य करने की योजना है।

Trade bodies eye sops for MSMEs, startups

On the eve of the Union Budget, which will be presented in Parliament on 1.2.2020. trade and Industries bodies in the state have expressed the hope that the micro, small and medium enterprises (MSME) sector- mainstay of Bihar's industrial sector- will receive a boost with enhanced monetary incentives.

P. K. Agarwal, President of Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI), sought enough incentives for the MSME sector, which makes a "significant contribution to the gross domestic product (GDP) of the country".

Agrawal said, "Despite making significant contribution to the growth of the economy, the MSME sector faces several problems, including lack of enough incentives from the government"

Agarwal added, "Corporate tax rates for the existing companies, which as of now is 22% should be slashed and made equivalent to the tax rates paid by new domestic manufacturing companies, which is 15%." **(Source : The Times of India, 1.2.2020)**

सिख समुदाय के लिए तोहफा है 'बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे'

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ एवं पुस्तकों का संच भेंटकर स्वागत करते प्रभात प्रकाशन के डॉ. पियुष कुमार। साथ में प्रभात खबर के पत्रकार एवं पुस्तक के लेखक श्री सुबोध कुमार नन्दन एवं अन्य अतिथिगण।

सुबोध नंदन की पुस्तक 'बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे' सिख समुदाय के लिए एक तोहफा है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रविवार दिनांक 23 फरवरी 2020 को आयोजित पुस्तक के विमोचन समारोह में चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने आगे कहा कि सुबोध खोजी पत्रकार रहे हैं और पुस्तक में उनके इस गुण की पूरी छाप दिखती है। उन्होंने प्रदेश के 22 गुरुद्वारे को न केवल खोज निकाला है, बल्कि उनका पूरा विवरण भी दिया है।

प्रभात प्रकाशन की इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में सरदार जगजीवन सिंह बादशाह ने कहा कि आज से पहले तक मुझे बिहार में सिर्फ नौ गुरुद्वारों के होने की जानकारी थी, लेकिन आज मालूम हुआ कि यहाँ 22 गुरुद्वारे हैं। पुस्तक को पढ़ने से मुझे ही नहीं बल्कि मेरी आगे आने बाली पीढ़ी को भी इसके बारे में विस्तार से मालूम होगा। आर. एस. जीत ने बिहार संगत की ओर से लेखक को बधाई देते हुए कहा कि उनकी पुस्तक में गुरू नानक से लेकर तेग

"बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे" पुस्तक का विमोचन करते सम्मानित अतिथिगण

बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के जन्म तक का पूरा इतिहास दिया गया है। बिहार सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह बग्गा ने कहा कि पुस्तक में सिख गुरुओं की बिहार यात्रा से संबंधित कई ऐसी बातें हैं जिन्हें अब तक ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। मधुसूदन ने कहा कि पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि बिहार में सिख गुरु आये तो कहाँ गये और क्या किया? गुरुदयाल सिंह ने कहा कि यह पहली पुस्तक है, जिसमें हर गुरुद्वारे की विस्तार से जानकारी दी गयी है। बीआइए के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि लेखक का प्रयास प्रशंसनीय है। बीआइए के पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा कि लेखक में हमेशा कुछ नया

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयें से चौथे)। साथ में मंचासीन प्रभात खबर के अधिकारीगण एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण

करने की ललक है। इससे दूसरे पत्रकारों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रभात प्रकाशन के एमडी पीयूष कुमार ने बिहार के लेखकों के 200 से भी अधिक पुस्तकों का अब तक प्रकाशन करने का जिक्र कर स्थानीय लेखकों को बढ़ावा देने की बात कही। लेखक सुबोध नंदन ने पुस्तक लेखन के क्रम में कटिहार, मुंगेर, सासाराम और पूर्णिया के भ्रमण का जिक्र करते हुए इसमें छह-सात साल लगने की बात कही। मौके पर तख्त हरमंदिर साहिब के सचिव महिंदर सिंह छाबड़ा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह, इएसआइसी के निदेशक अरविंद कुमार, आइओसी की मुख्य प्रबंधक वीणा कुमारी, डॉ सुदर्शन, डॉ अमित कुमार, एन. के. ठाकुर, संजय भरतिया, सुबोध जैन, मुकेश जैन, संदीप सर्राफ, आशीष अग्रवाल, पशुपति नाथ पांडेय आदि मौजूद थे। मंच संचालन साहित्यकार डॉ ध्रुव कुमार ने किया। सुबोध कुमार नंदन की यह तीसरी पुस्तक है।

(साभार : प्रभात खबर, 24.2.2020)

व्यापारियों को मिला उम्मीद से काफी कम

आम बजट 2020-21 का लाईव प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। बीसीसीआई सभागार में चैम्बर सदस्यों ने बजट देखने के बाद आयोजित चर्चा में बजट को कृषि आधारित बजट करार दिया है। बजट व्यापारिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है। बजट चर्चा में चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर, महामंत्री अमित मुखर्जी, चैम्बर के पूर्व महामंत्री पशुपति नाथ पांडेय, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, सुनील सर्राफ आदि मौजूद थे।

किसानों को होगा फायदा : चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि वजटीय घोषणाओं से किसानों, छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि राज्य के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से लोग निराश हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार के बजट में देश को आर्थिक मंदी से उबारने पर विशेष जोर दिया जाएगा लेकिन पूरे बजट को सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि इससे देश की आर्थिक मंदी से उबरने में बहुत अधिक सहायक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यामियों व व्यवसायियों को आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट को बीसीसीआई की तरफ से कई सुझाव दिए गए थे। इनमें पाँच सितारा होटल खोलने के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों में पाँच साल के लिए कर वसूली से छूट देने, पटना एयरपोर्ट के आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने, बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के कार्य में तेजी लाने, बिना कम्प्यूटर वाले व्यवसायियों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए सब्सिडी देने, जीएसटी मित्र बनाने, निःशुल्क सॉफ्टवेयर देने, जीएसटी अनुपालन करने वाले व्यवसायियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके खाते में कैश बैक की सुविधा देना आदि शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन संपूर्ण सामाजिक उत्थान की दृष्टि से बजट सराहनीय कहा जा सकता है।

बैंक गारंटी सीमा को 5 लाख करने की घोषणा का स्वागत : चैम्बर सदस्यों ने बजट में डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कंपनी के बदले व्यक्तिगत करने, सूक्ष्म इकाइयों के लिए 5 करोड़ तक ऑडिट से छूट, किसानों के लिए 16 सूत्री लाभकारी योजना, निवेश क्लीयरेंस सेल की स्थापना, बैंक गारंटी की सीमा को 5 लाख किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2020)

आम बजट 2020-21 पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

देश के बिहार पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आम बजट में डिविडेन्ट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कम्पनी के बदले व्यक्तिगत किये जाने, सूक्ष्म इकाइयों के लिए पाँच करोड़ तक ऑडिट से छूट। किसानों के लिए 16 सूत्री लाभकारी योजना, निवेश को आसान बनाने के लिए इनवेंस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की स्थापना, देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को अपग्रेड करने एवं तेजस जैसी ट्रेनों से जोड़ने, बिजली उपभोक्ताओं को सप्लायर चुनने का अधिकार, टैक्स पेयर की सुविधा हेतु टैक्स पेयर चार्टर का गठन एवं प्रत्यक्ष कर में विवाद से विश्वास योजना एवं बैंक गारंटी की सीमा को पाँच लाख किए जाने जैसी घोषणा स्वागतयोग्य कदम है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.2.2020)

इस बार के बजट से काफी अपेक्षाएँ थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार के आम बजट में देश को आर्थिक मंदी से उबारने पर विशेष जोर दिया जायेगा। लेकिन पूरे बजट का अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह बजट आर्थिक मंदी से उबरने में बहुत अधिक सहायक होगा। आयकर के स्लैब में बदलाव से कुछ लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी, जो इस ऑप्शन को अपनायेंगे, लेकिन इससे बचत पर प्रभाव पड़ेगा। बजटीय घोषणाओं से किसानों एवं छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि बिहार राज्य के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमें थोड़ी निराशा जरूर हुई है। बिहार की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों को ऐसी आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जायेगी, क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयलटी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2020)

इस बजट में बिहार की चर्चा नहीं है। न ही कोई स्पेशल पैकेज है। नए घोषणा आदि भी नहीं है। जबकि उद्योग से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : आईनेक्स्ट, 2.2.2020)

बजट में गाँव एवं गरीबों पर फोकस

बजट गाँव एवं गरीबों पर फोकस है। इससे ग्रामीण भारत को काफी लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों के लिए 16 सूत्री लाभकारी योजना की घोषणा की है। इसका लाभ किसानों को निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने 5करोड़ तक के ईकाइयों को ऑडिट से छूट दी है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बीसीसीआई

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2020)

बिहार के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से निराशा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि बजट 2020 में की गई घोषणा से किसान, छोटे और मध्यमवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन बिहार के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से निराशा हुई है। हालांकि सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान के हिसाब से इस बजट को सराहनीय कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट से काफी अपेक्षाएं थी। **– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष,** बीसीसीआई

(साभार : दैनिक भास्कर 2.2.2020)

Trade and industry hail proposals for agri sector

Trade and industry in the state had mixed reactions on the Union Budget, While some trade bodies praised the announcements for the agriculture sector and changes in income tax slabs, others expressed disappointment over less focus on micro, small and medium enterprises (MSME), and cooperative industries.

Bihar Chamber of commerce and Industries (BCCI) President P. K. Agarwal said, "We had expected special packages for MSMEs and small-scale units.

(source : T.O.I., 2.2.2020)

Trade and industry body, Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI), also expressed its concerns over the Budget giving a skip to Bihar's interests, saying there was no mention of any provision for the concept of industrially backward area grant fund which a backward state like Bihar was eagerly awaiting.

BCCI president P. K. Agrawal, however, welcomed the reduction in income tax rates and raising the threshold limit for audit of MSME sector units from ₹ 1 crore to ₹ 5crore.

(source : Hindustan Times, 2.2.2020)

स्थानीय उत्पादों की खरीद से सुदृढ़ होगा देश

• बेहतर भविष्य के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद को आंदोलन बनाने पर दिया जोर • वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत

आजादी के बाद के लोकप्रिय नारे 'भारतीय बनो, भारतीय खरीदो' को नया कलेवर देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'बेहतर भविष्य के लिए स्थानीय उत्पाद खरीदने' को एक आंदोलन के रूप में तब्दील करने का आहवान किया है।

राष्ट्रपति ने बजट सत्र की शुरुआत में अपना अभिभाषण देते हुए हरेक भारतीय से स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। कोविंद ने कहा, 'स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल कर आप अपने इलाके में मौजूद छोटे उद्यमियों की बड़ी मदद करेंगे।' उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आजादी का बुनियादी मंत्र रहा है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 1.2.2020)**

आर्थिक सर्वेक्षण ने दिए बजट के सात संकेत

• संसद के पटल पर 29.2.2020 को आर्थिक समीक्षा रखी गई • अर्थव्यवस्था का बुरा दौर खत्म, अब तेजी आने की बारी • 63वें स्थान पर कारोबारी सुगमता रैंकिंग में वर्ष 2019 में भारत • 23 पैसे का घाटा हुआ सरकारी बैंकों को एक रुपये के निवेश पर • 05 फीसदी रह सकती है चालू वित्त वर्ष में जीड़ीपी की विकास दर

सरकार के लिए इस बार बजट बेहद चुनौतीभरा हो सकता है। हालांकि, आर्थिक समीक्षा में ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार चुनौतियों के बावजूद रोगजार के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकता है।

आर्थिक समीक्षा में मिले संकेतों के अनुसार, सरकार आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाकर वर्ष 2024-25 तक पाँच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। बजट से उम्मीद है कि विशेषकर मध्यम वर्ग, की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर में बड़ी राहत दी जा सकती है लेकिन इससे राजस्व संग्रह प्रभावित हो सकता है। विश्लेषक ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री कॉरपोरेट कर में कमी की तर्ज पर आयकर में भी छूट देकर लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है। उनका कहना है कि ढाई लाख रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक के पहले स्लैब पर कर की दर पाँच फीसदी बनी रह सकती है, लेकिन पाँच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर कर को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, एसएमई आदि के लिए कई तरह की रियायतें देने की धोषणा हो सकती है।

रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को बड़ी रियायत मिलने की संभावना : अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ सरकार को रोजगार के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सरकार ने इसके लिए पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को बजट में बड़ी रियायत दे सकती है। इनमें विनिर्माण, इंफ्रा और सेवा क्षेत्र प्रमुख हो सकते है।

घटते कर संग्रह को पूरा करने के लिए विनिवेश पर जोर होगा : विशेषज्ञों का कहना है बजट में विनिवेश पर जोर रह सकता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था। हालांकि, उसको पाना अब संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में अच्छी कंपनियों में विनिवेश के जरिये ज्यादा बेहतर राजस्व हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार इसपर गौर करेगी जिससे लक्ष्य हासिल होगा।

इंफ्रा, रोड और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ सकता है बजट आवंटन : देश को वर्ष 2025 तक पाँच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इंफ्रा, रोड और ऊर्जा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रा क्षेत्र में अगले पाँच साल में 1.4 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत होगी। इस क्षेत्र के विकास से रोजगार में वृद्धि भी जुड़ी हुई है। इंफ्रा क्षेत्र सीधे तौर पर सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है।

बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती पर जोर : बैंकों में हाल के वर्षों में कई घोटाले सामने आए हैं जिससे उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। दुनिया के 100 शीर्ष बैंकों में एकमात्र एसबीआई ही है। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती पर बजट में जोर रह सकता है।

आयकर छूट में राहत की उम्मीद : अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए कई विशेषज्ञ व्यक्तिगत आयकर में छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं। इससे मदद मिलेगी जिसका लाभ अर्थव्यवस्था को होगा। कर में कटौती के बाद केन्द्र व्यक्तिगत करदाताओं को छूट दे सकता है।

छोटे उद्योगों को राहत की आशा : देश में रोजगार देने में सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान समय में यह चुनौतियों से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र के लिए कर्ज मिलना आसान करने पर घोषणा संभव है। इससे रोजगार के अवसर बढेंगे।

निर्यात बढ़ाने पर ऐलान संभव : भारत के निर्यात की रफ्तार सुस्ती के दौर से गुजर रही है। विनिर्माण से जुड़े क्षेत्रों को रियायत देकर निर्यात को रफ्तार दी जा सकती है। इसके निर्यात हिस्सेदारी बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.2.2020)**

आम बजट : 2020-21 की खास बातें

"अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है। महँगाई को रोकने में हम कामयाब रहे हैं। हमने कई संस्थागत सुधार किए है, जिनमें जीएसटी ऐतिहासिक रहा है।"

– निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

₹ 5,00,000 तक बैंक में जमा धन की इश्योरेंस गारंटी मिलेगी। अगर बैंक डूबता है तो पहले आपके एक लाख रुपये सुरक्षित रहते थे लेकिन अब ऐसी स्थिति में आपकी पाँच लाख रुपये तक की जमा रकम वापस मिल जाएगी।

• आधार कार्ड के आधार पर तत्काल पैन कार्ड के ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए कोई आवेदन फार्म जरूरी नहीं होगा।

• सरकार जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में अपना कुछ हिस्सा बेचकर कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। सरकार आइडीबीआइ बैंक से भी पूरी तरह बाहर हो जाएगी।

सुशिक्षित समाज : • शिक्षा क्षेत्र के लिए 9,300 करोड़, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रूपये आवंटित • पहली बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से धन जुटाया जाएगा। बाहर से वाणिज्यिक कर्ज जुटाने का रास्ता भी खुला • शीर्ष 100 शिक्षण संस्थान डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करेंगे।

जल संरक्षण : • स्थानीय जल स्रोतों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संचयन किया जाएगा • पानी की कमी की समस्या वाले 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे • हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम चल रहा है। इसके लिए 3.6 लाख करोड़ दिए जाएंगे।

जनसंख्या नियोजन : • अराजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए बनेगा 'नेशनल रिक्रूटमेंट सेंटर' • 112 सबसे पिछड़े जिलों को 'टेस्ट सेंटर' खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी • 2025 तक चार करोड़ और 2030 तक आठ करोड़ बेहतर सेलरी वाली नौकरियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य। 'स्टार्टअप' कंपनियों के लिए कर छूट की घोषणा।

गरीबी उन्मूलन : • पोषण अभियान के लिए खर्च किए जाएंगे 35,600 करोड़ रुपये। इससे महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण अभियान शुरू किया जाएगा • देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी। सरकार का इस पर विशेष ध्यान है • गरीबों को घर के पास मुहैया कराएँगे मुफ्त इलाज।

नारी सशक्तिकरण : • महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे • मातृत्व की उम्र तय करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। टास्क फोर्स छह महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी। लड़कियों की शादी करने की उम्र बढ़ सकती है • छह लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को स्मार्ट फोन दिए गए।

पर्यावरण संरक्षण : • 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को साफ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है • कोयले वाले पावर प्लांटों को जल्द से जल्द बंद किया जाएगा • जलवायु परिवर्त्तन पर इंटस्नेशनल सोलर एलायंस को मजबूती देकर आ रही चुनौतियों का सामना किया जाएगा।

स्वस्थ समाज : • पीएम जनआरोग्य योजना के तहत टियर-2 और टियर - 3 शहरों में पीपीपी मॉडल से जनआरोग्य अस्पताल खुलेंगे • पहले चरण में 112 जिलों से इसकी शुरूआत होगी। जिन जिलों में एक भी अस्पताल पैनल में नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी • मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाया जाएगा।

बूस्टर डोज : • पाँच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी केन्द्र सरकार • देश में पाँच नई स्मार्ट सिटी बनाएगी सरकार • 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसापोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे • रेल और विमानन मंत्रालय चलाएंगे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर परिवहन सेवाएं। देश में कई जगहों पर पीपीपी मॉडल से बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोरेज • किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने बनाया 17 सूत्रीय प्लान

आपके खाते में : • 5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10% , 7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर अब 20% टैक्स लगेगा • 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर पहले की तरह ही 30% की दर से टैक्स लगता रहेगा • अब अगले साल 31 मार्च तक हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकेगा। सरकार ने समयसीमा बढ़ा दी है।

उद्योगों की उन्नति : • उद्योग जगत और कारोबारी विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपये का प्रावधान, छोटे-मेझोले उद्योगों को विदेशी बाजार में उतारने की तैयारी • मोबाइल, इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा • 1480 करोड़ रुपये टेक्सटाइल मिशन के लिए आवंटित होंगे, 22 हजार करोड़ रुपये पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित • डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से मुक्ति मिलेगी। इससे निवेशक भारत में निवेश के लिए आकर्षित होंगे।

बेहतरी की राह : • उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा • निजी क्षेत्र की मदद से डाटा सेंटर पार्क बनाएंगे • रेल पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनेगा • 150 ट्रेने पब्लिक- प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होंगी। तेजस जैसी कई ट्रेनें चलाई जाएंगी • आने वाले वक्त में देशभर में प्री पेड मीटर लगेंगे। यह स्मार्ट मीटर होगा। जिसकी मदद से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा • एक लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

बुलंद वुनियाद : • सरकार ने रक्षा बजट में की गई 5.83 फीसद की बढ़ोतरी • चीन की जगह लेने की पूरी तैयारी • आएगा 1,550 किलोमीटर राजमार्गों का नया त्वरित कार्यक्रम।

सुधारों का सिलसिला : • सरल और साफ होगी कर व्यवस्था, अपराधी बनाने वाले प्रावधानों से छुटकारा • बैंक डिपॉजिट को मिली बड़ी गारंटी • विश्वास के सहारे कम होगा विवाद का बोझ, नई योजना लांच।

रोजगार की राह : • युवाओं के लिए रोजगार का विशेष प्रावधान किया गया • देश में नदियों के किनारे बडेगी अर्थगंगा • सभी की पहुँच में उच्च शिक्षा, शुरू होंगे ऑनलाइन डिग्री कोर्स

न्यू इकोनॉमी : • चौथे दौर की औद्योगिक क्रांति का मंत्र, न्यू इकोनॉमी को धार देने की कोशिश • नॉमिनल ग्रोथ रेट से पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर कदम • विदेशी सॉवरेन फंडों को कर राहत।

खजाने की खातिर : • रेवेन्यू के लिए विनिवेश पर बढ़ाया भरोसा • आर्थिक हालात देखकर राजकोषीय संतुलन किया नजरअंदाज • निजी क्षेत्र के लिए अलग पेंशन ट्रस्ट बनाने की तैयारी।

सशक्त समाज : • गुणवतापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की राह में पैसा नहीं बनेगा बाधा • डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी दूर करने की ठोस पहल • पढ़ रही है बेटियाँ, बढ़ रही है बेटियाँ।

गाँव की ओर : • किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ी सरकार • सफलता की रेल से तरक्की की उड़ान, सरकार ने बढ़ाए कदम • विश्व कृषि बजार के आसान रास्ते।

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2020)

सस्ता-महंगा

ये होगा महंगा : घी, मक्खन, खाद्य तेल, छाछ, चीनी, मक्का, संरक्षित आलू, सोयाबीन, फुटवियर, हेयर क्लिप, शैम्पू, अखरोट, रसोई सामग्री, कांच का सामान, माणिक, पन्ना, नीलम, ताला, छलनी, छत और दीवार वाले पंखे, ब्लोअर, टोस्टर, हीटर, इमल्शन रॉड, हेयर ड्रायर, प्रेस, ग्राइंडर, ओवेन, कुकर, लैंप, फर्नीचर, स्टेशनरी, घंटियां, खिलौने, मोबाइल फोन

ये होगा सस्ता : रॉ शुगर, स्किम्ड मिल्क, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन, कृषि-पशु आधारित उत्पाद, प्यूरीफाइड टेरिफैलिक एसिड, अखबार का कागज, कोटेड पेपर

एक्साइज बढ़ाया : सिगरेट, हुक्का, तंबाकू

इक्साइज घटाया : खेल का सामान, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, समाचार पत्र

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2020)

बजट : एक नजर में (राशि करोड़ में)

विषय	2018-19 वास्तविक	2019-20		2020-21 बजट अनुमान
		अनुमान	सं. अनुमान	
1. राजस्व प्राप्तियां	15,52,916	19,62,761	18,50,101	20,20,926
2. कर राजस्व	13,17,211	16,49,582	15,04,587	16,35,909
3. कर भिन्न राजस्व	2,35,705	3,13,179	3,45,514	3,85,017
4. पूंजी प्राप्तियाँ	7,62,197	8,23,588	8,48,451	10,21,304
5. ऋणों की वसूली	18,052	14,828	16,605	14,967

6. अन्य प्राप्तियां	94,727	1,05,000	65,000	2,10,000
7. उधार और अन्य देयताएं	6,49,418	7,03,760	7,66,846	7,96,337
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	23,15,113	27,86,349	26,98,552	30,42,230
9. कुल व्यय (10+13)	23,15,113	27,86,349	26,98,552	30,42,230
10. चालू खाते पर	20,07,399	24,47,780	23,49,645	26,30,145
11. ब्याज भुगतान	5,82,648	6,60,471	6,25,105	7,08,203
12. पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	1,91,781	2,07,333	1,91,737	2,06,500
13. पूंजी खाते पर	3,07,714	3,38,569	3,48,907	4,12,085
14. राजस्व घाटा (10-1)	4,54,483	4,85,019	4,99,544	6,09,219
15. प्रभावी राजरव घाटा (14-12)	2,62,702	2,77,686	3,07,807	4,02,719
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	6,49,418	7,03,760	7,66,846	7,96,337
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	66,770	43,289	1,41,741	88,134

(साभार : दैनिक जागरण, 2-2-2020)

ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार : चैम्बर

बिहार देश में ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्पष्ट है कि सरकार जलजीवन हरियाली पर विशेष बल देगी जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में करीब 6 प्रतिशत की वृद्धि कर 2,11,761 करोड़ किया जाना स्वागतयोग्य है। इससे राज्य के विकास कार्यों में गति मिलेगी। राज्य में नये मेडिकल कॉलेज खोलने एवं वर्तमान अस्पतालों में बेडों की संख्या में बढ़ोतरी, सभी जिलों में महिला पॉलिटेक्निक खोलने, सभी सरकारी भवनों की छत पर वर्षा जल संचय योजना प्रारम्भ करने, नयी सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, दरभंगा, बिहटा एवं पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास, राज्य के नौ जिला अस्पतालों का मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन, हर घर में नल का जल एवं नाली-गली पक्कीकरण योजना का मार्च 2020 तक पूरा करने की योजना स्वागतयोग्य है।

बजट पूर्व बैठक में राज्य सरकार से उद्योग विभाग का बजट 2000 करोड़ करने, जिससे उद्योगों के पूर्व के क्लेम का निपटारा किया जा सके, औद्योगिक विकास निधि का गठन करने, लैंड बैंक बनाने, बैंकों पर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का दवाव बनाने, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को पर्यटन स्थल का दर्जा देने, राज्य में खाद्य तथा खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पादन की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात के लिए एक सहयोगी संस्था का गठन करने, खरीद अधिमानता नीति का कार्यान्वयन सही तरीके करने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए नियम बनाने एवं मास्टर प्लान में उद्योगों के लिए अलग से स्थान चिह्नित करने आदि मांग की गयी थी।

चैम्बर ने राज्य में लागू विद्युत दरें पड़ोसी राज्यों यथा झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के समतुल्य करने अथवा राज्य में स्थित उद्योगों को सब्सिडी देने, आईटी के लिए नीति निर्धारण करने एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने, बियाडा द्वारा भी उद्योगों को दी गयी जमीन को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करने, फैक्ट्री लाइसेंस के लिए ओटीएस योजना लाने एवं सरकार की पॉलिसी का समयबद्ध कार्यान्वयन कराने आदि सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 26.2.2020)

बिहार बजट : 2020-21 की खास बातें

गाँवों पर दांव : • 2.12 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ विस में • 250 से अधिक आबादी वाले गाँवों तक पक्की सड़क • 73 योजनाओं में से 21 हैं गाँवों पर केंद्रित • राज्य सरकार का सर्वाधिक जोर गाँवों के विकास पर • कई विभागों के बजटीय प्रावधानों का सीधा लाभ गाँवों को • ग्रीन बजट इसी सत्र में लाने का एलान किया गया • सिंचाई के लिए किसानों को अलग से बिजली दी जाएगी

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिनांक 25.2.2020 को विधानमंडल के दोनों सदनों में वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। 2.11 लाख करोड़ के बजट का बड़ा हिस्सा गाँवों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, जल संसाधन, पीएचईडी विभागों को भरपूर राशि उपलब्ध कराई गई है। इनके अलावा कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और सहकारिता के बजटीय प्रावधान का बड़ा हिस्सा गाँवों पर खर्च होगा। राज्य सरकार ने इसी सत्र में ग्रीन बजट लाने की भी घोषणा की है। गाँवों को उसका भी लाभ मिलेगा।

"वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बाद भी बिहार ने दहाई अंकों में विकास दर हासिल की है, जो वर्तमान मूल्य पर 15 फीसदी है।"

– **सुशील कुमार मोदी,** वित्त मंत्री, बिहार

तैयारी : इन योजनाओं से गाँवों का कायाकल्प

• 8549 करोड़ खर्च करेगी सरकार गाँवों के गरीबों का घर बनाने के मद में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनेंगे • 8518 करोड़ खर्च होंगे गाँवों की सड़कों को चकाचक करने के लिए, जबकि ग्रामीणों के हरेक घर में नल का जल पहुँचाने के लिए 5246 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन : मनरेगा में 2785 करोड़ तो गाँवों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1606 करोड़ खर्च होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1566 करोड़ का प्रावधान।

जैविक खेती और डेयरी : जैविक खेती, किसानों को प्रशिक्षण आदि मद में 675 करोड़, डेयरी के विकास मद में 174.68 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 1353 करोड़ का प्रावधान।

किसे क्या मिला

ऊर्जा : किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली देने की 5827 करोड़ की योजना के तहत 267 पावर सबस्टेशन, 1312 फीडर बनेंगे। किसानों को बिजली कनेक्शन भी मिलेगा।

पुल-पुलिया : सरकार पुल-पुलियों पर भी जोर दे रही है। नीतीश सरकार के प्रयासों का असर है कि बन चुके या बनने वाले पुलों को मिला दें तो केवल गंगा नदी पर ही 13 पुल बन जाएंगे।

प्रशिक्षण : कुशल युवा कार्यक्रम के तहत राज्य के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 9.50 लाख से अधिक को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना जारी रहेगी।

नगर विकास : स्मार्टसिटी मिशन योजना के लिए 620 करोड़ मिलेंगे। शहरी पुनर्नवीकरण-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 610 करोड़ का प्रावधान।

उद्योग : मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा उद्यमी योजना के लिए 225.96 करोड़ और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना के लिए 200.84 करोड़ बजट में दिए गए हैं।

पर्यावरण : राज्य में ईको टूरिज्म और पर्यावरण पर विशेष फोकस। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की अलग संभाग बनेगा। वहीं, सरकारी नर्सरियों में वर्ष 2020 में आठ करोड़ पौधे उगाए जाएंगे।

किसान : फसल सहायता योजना के तहत खरीफ के लिए 24.94 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस वर्ष 34,422 किसानों से 2,60,527 मैट्रिक टन धान की खरीद हुई है।

डेयरी : राज्य में दूध का उत्पादन 19.41 लाख लीटर रोजाना हो गया है। दूध का दैनिक विपणन 15.05 लाख लीटर हो गया है। राज्य की पशु संपदा में 10.67 प्रतिशत की वृद्धि।

अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनेंगे : • अनाज के भंडारण के लिए 150 करोड़ की लागत से गोदाम बनाए जाएँगे • अब तक 1,36,573 किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है • छात्रों को तकनीक से लैस करने के लिए विश्वविद्यालय व कॉलेजों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा • स्वच्छ भारत अभियान के लिए 240 करोड़ • पटना मेट्रो के लिए 50 करोड़ का बजट में प्रावधान।

शहरों में सबके लिए घर, 11 और मेडिकल कॉलेज : • शहरों में सबके लिए आवास योजना के मद में 425 करोड़ का प्रावधान • 8,463 पैक्सों में 1.20 करोड़ किसान सदस्य, इनमें 36 लाख महिलाएँ • 13 पुल राज्य सरकार ने बनाए कोसी नदी पर चार पुल चालू हुए और दो पुल स्वीकृत हैं • एनडीए सरकार ने चार मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, 11 और ऐसे कॉलेज खोले जा रहे हैं।

ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य होगा बिहार : सरकार इस बार ग्रीन बजट भी पेश करेगी। देश में बिहार पहला राज्य होगा जो ग्रीन बजट पेश करेगा। सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना जल-जीवन-हरियाली के तहत 24 हजार 500 करोड़ खर्च करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। पेश होने वाले ग्रीन बजट में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का ब्योरा होगा। वैसे सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को ग्रीन बजट में शामिल किया जाएगा जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों की रोकथाम के लिए जरूरी है। अब तक सरकार महिलाओं के लिए जेंडर बजट व बच्चों के लिए बाल बजट पेश करती रही है। ग्रीन बजट के कारण आम बजट से हटकर इस बार तीन और बजट पेश होंगे।

यातायात : 6706 करोड़ से चमकेंगी सड़कें : • 1990 से 2005 तक सड़कों पर मात्र 4124 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं वर्ष 2006 से 2020 के बीच 64 हजार 752 करोड़ सड़कों पर खर्च हुए। • वित्तीय वर्ष 2020-21 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6706 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें योजना मद में 5581 करोड़ तो वेतन, पेंशन आदि स्थापना मद में 1125 करोड़ खर्च होंगे। • साल 2005 के पहले गंगा नदी पर मात्र तीन पुल थे। आने वाले दिनों में 13 पुल हो जाएंगे। जबकि भेजा-बकौर, वीरपुर-बिहपुर के बीच चार लेन पुल भी मंजूर हुआ है। • कोसी नदी पर ही फुलौत में चार लेन पुल का काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। विक्रमशिला सेतु और गाँधी सेतु के समानांतर पुल निर्माण का भी काम शुरू होगा। • प्रधानमंत्री की ओर से घोषित सवा लाख करोड़ के बिहार पैकेज में सड़क मद में 53 हजार करोड़ दिए गए। 75 योजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी हैं। 40 टेंडर की प्रक्रिया में है। बाकी योजनाओं पर काम जारी है।

नौ जिला अस्पताल बनेंगे मॉडल अस्पताल : 172.95 करोड़ रुपये की लागत से नौ जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाने का प्रावधान किया है। दरभंगा में 45 करोड़ की लागत से सौ बेड वाले सदर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। पटना स्थित आईजीआईएमएस को सरकार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करेगी। बिहार में बिल-मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की योजनाओं का पाँच वर्षों के लिए विस्तार किया गया है।

शिक्षा सर्वोपरी : राज्य बजट में शिक्षा सर्वोपरी स्थान पर है। कुल बजट का 16.62% शिक्षा पर निर्धारित किया गया है। शिक्षा पर 35,191.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान 26.2.2020)

बजट सार - 2020-21
(आय-व्यय एक दृष्टि में)

मद		बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तियाँ	183923.99
2	कर राजस्व (क+ख)	125930.60
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	91180.60
	(ख) राज्य सरकार के कर राजस्व	34750.00
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	5239.28
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	52754.10
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ [5 (ग)+6+7+8]	28037.50
5	(ग) आकस्मिकता निधि को अंतरण	0000.00
6	ऋणों की वसूली	428.23
	लोक ऋण (7+8)	27609.27
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	24809.27
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2800.00
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	211961.49
10	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	105995.14
11	राजस्व खाते पर जिसमें	98784.05
12	(क) ब्याज भुगतान	12924.65
12	(ख) पेंशन	20468.16
12	(ग) वेतन	24987.14
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)	7211.09
	(क) राज्य का आंतरिक ऋण	5920.06
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1115.22
	(ग) पूंजीगत व्यय	61.39
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	114.43
	(च) आकस्मिकता निधि को अंतरण	000.00
14	(क) राज्य स्कीम	44976.94
14	(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केंद्रांश एवं राज्यांश राशि	55874.26
14	(ग) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	504.01
14	(घ) वाहय संपोषित परियोजनाओं के राज्यांश एवं ऋण तथा अनुदान की राशि संबंधित व्यय	4411.14
14.	स्कीम व्यय (क+ख+ग+घ)	
15.	राजस्व खाते पर	105766.35
16.	पूंजीगत खाते पर	65967.14
17.	कुल व्यय (10+14)	39799.21
18.	राजस्व व्यय (11+15)	211761.49
19.	पूंजीगत व्यय (13+16)	164751.19
20.	राजस्व घाटा (18-1)	47010.30
21.	राजकोषीय घाटा ([17-(1+6+13 क+13 ख)]	-19172.80 20373.99
22.	प्राथमिक घाटा (21-12क)	7449.34
23.	जीएसडीपी	685797.00
24.	राजकोषीय घाटा / जीएसडीपी	02.97
25.	ब्याज भुगतान / कुल राजस्व प्राप्तियाँ	07.03

(नोट : राशि करोड़ में)

2020-21 रुपया आता है : • राज्य सरकार के कर राजस्व 16.39 • केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 43.02 • ऋणों की वसूली 0.20 • राज्य सरकार के कर राजस्व 2.47 • केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान 24.89 • लोक ऋण 13.03

2020-21 रुपया जाता है : • सहायता अनुदान 0.01 • आर्थिक सेवाएँ 25.90 • सामाजिक सेवाएँ 43.56 • लोक ऋण 3.32 • केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान 24.89 • ऋण और पेशगियाँ 0.58 (प्रतिशत में)

(साभार : हिन्दुस्तान 26.2.2020)

साल दर साल बढ़ता गया बजट आकार

वित्तीय वर्ष	बजट	वित्तीय वर्ष	बजट
2005-06	26,328	2013-14	92,087
2006-07	29,220	2014-15	1,16,886
2007-08	33,257	2015-16	1,20,685
2008-09	38,574	2016-17	1,44,696
2009-10	47,446	2017-18	1,60,085
2010-11	53,758	2018-19	1,76,990
2011-12	65,325	2019-20	2,00,501
2012-13	78,686	2020-21	2,11,761

(राशि करोड़ में)

पाँच प्रमुख विभाग, जिन्हें अधिक राशि आवंटित हुई : • शिक्षा - 35195.05 • ग्रामीण विकास विभाग - 15995.29 • स्वास्थ्य विभाग - 10937.68 • ग्रामीण कार्य विभाग - 10638.89 • पंचायतीराज विभाग - 10615.21 (राशि करोड़ में)

राजस्व बचत : वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19,172.80 करोड़ रुपये राजस्व बचत रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद 6,85,797 करोड़ रुपये का 2.80 प्रतिशत है।

राजकोषीय घाटा : वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20,374 .00 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,85,797.00 करोड़ रुपय का 2.97 प्रतिशत है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.2.2020)**

बिहार बनेगा इथेनॉल उत्पादन का हब, टूटे चावल और गेहूँ से भी होगा तैयार

बी-हैवी छोआ से इथेनॉल बनाने की अनुमति की अधिसूचना जारी, राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति - 2018 को ध्यान में रखकर सरकार ने लिया निर्णय

अब राज्य के डिस्टलरीज बी-हैवी छोआ (मोलासेस) से इथेनॉल बना सकती है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति -2018 के तहत भारत सरकार से मिले दिशा-निर्देश के बाद बी-हैवी छोआ से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दिया। राज्य में 1अप्रैल 2016 से लागू शराबबंदी कानून के तहत डिस्टलरीज छोआ (मोलासेस) से इथेनॉल बना रही है। अनाज आधारित डिस्टलरीज को केवल एक्सट्रा-न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) बनाने और बाद में अनाज से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी थी। सरकार के इस निर्णय से राज्य के डिस्टलरीज में और अधिक इथेनॉल का उत्पादन होगा। वही इस क्षेत्र में निवेश का वातावरण भी बनेगा।

चीनी उत्पादन कम होने की स्थिति में सी- मोलासेस से इथेनॉल बनाने का सुझाव

मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बी-हैवी छोआ (मोलासेस) से इथेनॉल बनाने की अनुमति देने से पहले गन्ना उद्योग विभाग से इस संबंध सुझाव मांगा था। गन्ना उद्योग विभाग ने उत्पाद विभाग को राज्य में चीनी का भंडार अधिक होने की स्थिति में बी-हैवी छोआ (मोलासेस) से इथेनॉल बनाने और भंडार कम होने पर सी-मोलासेस से इथेनॉल बनाने का सुझाव दिया है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर 11.2.2020)

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

आपकी जेब में फिर आएगा एक रुपये का नया नोट

सरकार एक रुपये के नोट को नए सुरक्षा फीचर के साथ जल्द बाजार में पेश करने वाली है। 7 फरवरी की एक अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय इसकी छपाई करने की तैयारी में है। इसमें कई वाटरमार्क यानी विशेष पहचान चिन्ह होंगे। इस नोट की खास बात यह है कि इसे अन्य भारतीय नोटों की तरह रिजर्व बैंक जारी नहीं करता बल्कि भारत सरकार ही इसकी छपाई करती है। इस पर वित सचिव का हस्ताक्षर होता है।

कीमत से ज्यादा है नोट छपाई की लागत : एक रुपये के नोट को छापने की लागत 1.14 रुपये बैठती है। वर्ष 2015 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में यह तथ्य सामने आया था। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि कानूनी आधार पर एक रुपये का नोट एक मात्र वास्तविक मुद्रा यानी नोट (करेंसी नोट) है। अन्य सभी तरह के नोट धारीय नोट (प्रॉमिसरी नोट) होते हैं जिस पर धारक को उतनी राशि अदा करने का वचन दिया गया होता है। **(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 15.2.2020)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296